भारत-आसियान सम्मेलन और इसके निहितार्थ

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत को शामिल और/या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते

प्रसंग

क्षेत्र के सर्वाधिक प्रभावशाली समूहों में से एक के रूप में विदित आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटवार्ता की और दोनों पक्षों ने सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया।

ज्ञातव्य है कि 10 राष्ट्रों के समूह आसियान के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

आसियान

स्थापना

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ अथवा आसियान 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में स्थापित किया गया था।

संस्थापक देश

इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ

सदस्य देश	
1.	इंडोनेशिया
2.	मलेशिया
3.	थाईलैंड
4.	सिंगापुर
5.	फिलीपींस
6.	ब्रुनेई दारुस्सलाम
7.	वियतनाम
8.	लाओस
9.	म्यांमार
10.	कंबोडिया

मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया

विमर्श के विभिन्न बिन्दु

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षागत मुद्दे

- भारत के विदेश मंत्रियों और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर यूक्रेन संकट के प्रभाव का आकलन करने और इसे संबोधित करने के विभिन्न तरीकों पर परिचर्चा की। साथ ही व्यापार, संपर्क, रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की।

निम्नलिखित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई

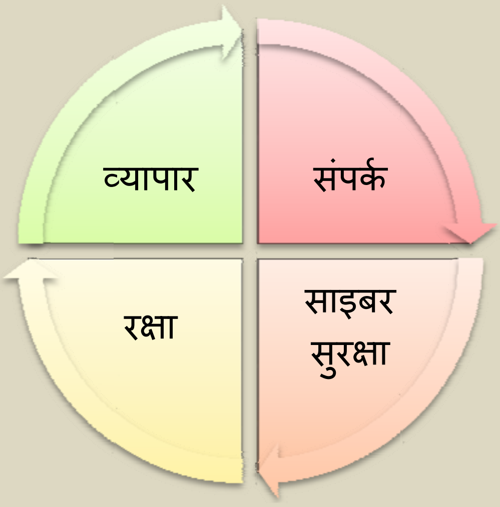

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- यह पहली बार था, जब भारत ने 10 सदस्यीय समूह के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की।
- बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके सिंगापुर के समकक्ष विवियन बालकृष्णन ने की।
- ध्यातव्य है कि भारत-आसियान के मध्य पारस्परिक संबंधों के 30 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन सम्पन्न हुआ।

कोविड -19 और इसके दुष्प्रभाव

- यूरोप में ऐसे समय में हुए घटनाक्रम से महामारी से उबरने की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जब कोविड -19 संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
- भू-राजनीतिक बाधाओं के कारण यूक्रेन में विकास प्रभावित हुआ है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव के कारण उर्वरक और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि दृष्टिगत हो रही है। साथ ही, रसद और आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)

- दोनों पक्षों ने मौजूदा भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने की दिशा में काम करने और समझौते को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरल बनाने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की शीघ्र समीक्षा शुरू करने हेतु सहमति व्यक्त की है।
- एआईटीआईजीए की समीक्षा के लिए स्कोपिंग पेपर के समर्थन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की गई, ताकि आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) संयुक्त समिति को एआईटीआईजीए समीक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सक्रिय किया जा सके।
- इन कदमों से आसियान-भारत व्यापार और आर्थिक साझेदारी की सर्वोत्तम क्षमता को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसमें एआईएफटीए का प्रभावी कार्यान्वयन भी शामिल है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता

क्या है?

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (Asean-India Free Trade Area- AIFTA) आसियान और भारत के दस सदस्य राज्यों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है।

कब प्रभावी हुआ?

- आसियान और भारत ने 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में 7 वें आसियान आर्थिक मंत्रियों-भारत परामर्श में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2010 में प्रभावी हुआ, जिसे कभी-कभी आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते के रूप में संदर्भित किया जाता है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना

- यह समझौता 2003 में बनाए गए भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते से उत्पन्न हुआ था।
- इस फ्रेमवर्क समझौते ने भविष्य के व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए भारत और आसियान के लिए आधार निर्धारित किया।
- समझौते में भौतिक वस्तुओं और उत्पादों में व्यापार शामिल है। यह सेवाओं में व्यापार पर लागू नहीं होता है।
- आसियान और भारत ने 2014 में एक अलग आसियान-भारत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- आसियान-भारत निवेश समझौते के साथ, तीन समझौते सामूहिक रूप से आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाते हैं।
- 2010 में समझौता लागू होने के बाद, इसने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक की स्थापना की, जिसमें करीब 1.8 बिलियन लोगों का संयुक्त बाजार शामिल था।
- समझौते के तहत आसियान और भारत ने 76.4 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क को उत्तरोत्तर समाप्त करने और 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर शुल्क को उदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

पारस्परिक संपर्क के विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया

- विदेश मंत्रियों ने आसियान कनेक्टिविटी (एमपीएसी) 2025 पर मास्टर प्लान और इसकी "एक्ट ईस्ट" नीति के तहत भारत की कनेक्टिविटी पहल के बीच सामंजस्य बढ़ाने के विभिन्न मार्गों की खोज करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- शामिल पक्षों ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को तेजी से पूरा करने और संचालित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इसे पूर्व की ओर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विस्तारित करने के साथ-साथ अधिक सुदृढ़ वायु और समुद्री संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया।

अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता

- 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) सहित अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए दोनों पक्षों ने एक नियम-आधारित क्षेत्रीय ढांचा विकसित करने में आसियान केंद्रीयता का समर्थन करने के लिए सहमत हुए।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र

- वे इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) और भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (आईपीओआई) विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम प्रबंधन, खोज और बचाव कार्यों और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के विभिन क्षेत्रों की खोज करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रस्तावित अनौपचारिक बैठक के साथ अन्य मुद्दों पर विमर्श

- नवंबर में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की एक प्रस्तावित अनौपचारिक बैठक और एक प्रस्तावित आसियान-भारत समुद्री अभ्यास के अतिरिक्त इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा हुई।
- विदित है कि भू-राजनीतिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं को देखते हुए आसियान की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

- एओआईपी और आईपीओआई के बीच मजबूत अभिसरण क्षेत्र दोनों पक्षों के मध्य साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है।

आसियान शिखर सम्मेलन

- आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान में सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है, जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार शामिल हैं।
- आसियान शिखर सम्मेलन अन्य आसियान सदस्य देशों के परामर्श से आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय में वार्षिक दो बार आयोजित किया जाता है।
- शिखर सम्मेलन की मेजबानी आसियान सदस्य देश द्वारा की जाती है।
- पहला आसियान शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था।

भारत-आसियान संबंध और महत्व

- आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी है।
- आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केन्द्र है।
- भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार, 1996 में संवाद भागीदार और 2002 में शिखर-स्तरीय भागीदार बना।
- पिछले दो दशकों में भारत-आसियान संबंधों के विकास के परिणामस्वरूप 2012 में साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।
- भारत ने 2014 में आसियान सदस्य देशों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की।
- भारत-आसियान के मध्य पारस्परिक संबंधों के 30 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन सम्पन्न हुआ।
- एक्ट-ईस्ट नीति में कनेक्टिविटी, वाणिज्य और संस्कृति के 3 सी पर अधिक से अधिक आसियान-भारत एकीकरण के लिए कार्रवाई के फोकस क्षेत्रों के रूप में बल दिया गया है।

- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत ने 2009 में माल में एफटीए और 2014 में आसियान के साथ सेवाओं और निवेश में एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए।
- भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।
- भारत, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय (आईएमटी) राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं चला रहा है।
- भारत आसियान के साथ एक समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है और भारत वियतनाम में हनोई में एक रेलवे लिंक की भी योजना बना रहा है।
- आसियान के साथ लोगों से लोगों की बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आसियान के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान-प्रदान आदि।
- भारत और अधिकांश आसियान देशों के बीच संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

भारत-आसियान संवाद तंत्र

- भारत और आसियान में अनेक संवाद तंत्र हैं, जिनका नियमित रूप से आयोजन किया जाता है, जिसमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।
- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने सितंबर 2021 में वर्चुअली आयोजित आसियान आर्थिक मंत्रियों + भारत परामर्श में भाग लिया, जहां मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

निष्कर्ष

- आरसीईपी समझौते से भारत का अलग होना, आसियान देशों के साथ संबंधों की सीमाओं को दर्शाता है। इन देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों दोनों के लिए आवश्यक है।
- ज्ञातव्य है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 10 सदस्य देशों ने 15 नवंबर 2020 को वियतनाम के हनोई में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर को लेकर एक वर्चुअल समारोह का आयोजन किया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट